बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 276

खाड़ी संकट में तैयारी

इराक दौरे पर गए ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हुई हत्या ने पश्चिम एशिया में हालात बिगाड़ दिए हैं। इस इलाके के सशस्त्र संघर्ष के मुहाने पर पहुंच जाने से तेल कीमतों में अचानक उछाल आई है। ईरानी सेना की विशिष्ट इकाई कुद्स फोर्स के मुखिया के रूप में सुलेमानी क्षेत्रीय राजनीति में अहम स्थान रखते थे और खुद ईरान के भीतर वह काफी लोकप्रिय एवं सशक्त थे। इस हत्या के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा होने पर अल्पावधि से लेकर मध्यम अवधि में तेल कीमतों के रुख को लेकर कोई भी अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका का शेल तेल उत्पादन तेज है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग कमजोर है। वैसे बाजार किसी भी तरह जरूरत से ज्यादा आपूर्ति की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन समस्या यह है कि सीमित संघर्ष में भी तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। आपूर्ति शृंखला से हटा देने पर तेल की किल्लत पैदा हो सकती है जिससे अल्पावधि से मध्यावधि के भीतर तेल कीमतें चढ़ सकती हैं।

इस तरह भारत सरकार को तीन पहलुओं पर ध्यान देते हुए अपनी तैयारियां करनी होंगी। ये पहलू कई दशकों से एकसमान रहे हैं और पश्चिम एशिया में स्थिरता पर भारत की निर्भरता का कारण भी हैं। पहला बिंदु तेल की आपूर्ति से जुड़ा है। भारत को अपनी 84 फीसदी तेल जरूरतें आयात से पूरी करनी पड़ती हैं। इस तरह तेल कीमतों में उछाल न केवल घरेलू लागत परिस्थितियों बल्कि भुगतान संतुलन पर भी बड़ा अंतर डालता है। तेल कीमतें बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक तौर पर स्फीतिकारी दबाव पड़ेंगे। लिहाजा भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरें तय करते समय कहीं अधिक सजगता दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अतीत में ऊंची तेल कीमतों ने बाह्य खाते को खासा कमजोर किया है। पश्चिम एशिया में 1991 में पैदा हुए ऐसे ही संकट के बाद भारत के समक्ष भुगतान संतुलन का संकट पैदा हुआ था जिसके बाद देश में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। आज 450 अरब डॉलर के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी सुविधाजनक स्थिति में है और तेल कीमतों के मौजूदा स्तर पर रहने पर इससे अगले नौ-दस महीनों तक तेल आयात का इंतजाम हो सकता है। अगर तेल कीमतों में लगातार एवं तीव्र वृद्धि होती है तो फिर इस बफर में सेंध लग सकती है। हालांकि दो पहलू ऐसे हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। इन दोनों का ताल्लुक पश्चिम एशिया खासकर फारस की खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय की मौजूदगी है। निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अतीत में भारत ने खाड़ी देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। पहले खाड़ी युद्ध के समय कुवैत और हाल में लीबिया से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया था। खाड़ी देशों से भारतीयों की सुरक्षित निकासी की योजना इस बार कहीं अधिक बड़े पैमाने पर अंजाम देनी होगी, वैसे ऐसी स्थिति आने की संभावना कम ही लग रही है।

हालांकि तनाव गहराने से आने वाली गिरावट के चलते बड़ी संख्या में अस्थायी कामगारों को भारत लौटना पड़ सकता है। ऐसा होने पर भारत को खाड़ी देशों से भेजा जाने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। वर्ष 2016-17 में अकेले संयुक्त अरब अमीरात से 27 फीसदी विदेशी धन भारत में आया था और अन्य खाड़ी देशों का भी योगदान 27 फीसदी रहा था। भारत आने वाली आधी से भी अधिक विदेशी मुद्रा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में आती है। धन की आवक में बड़ी कमी होने से बाह्य खाते एवं इन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा। लिहाजा भारत सरकार को खाड़ी के घटनाक्रम पर नजदीकी निगाह रखने के साथ अपनी तैयारियां भी रखनी होंगी।

अजय मोहंती

नए साल में कैसे होंगे भारत-अमेरिका संबंध

घरेलू मोर्चे पर भारत के हालात उसे चीन के बरक्स खड़ा करने की रणनीति की राह में रोड़े बन सकते हैं। नए साल में भारत-अमेरिकी संबंधों के भविष्य का जायजा ले रही हैं **अनीता इंदर सिंह**

नवनर्ष 2020 में भारत-अमेरिका संबंधों के लिए क्या परिदृश्य दिख रहा है? वर्ष 2006 में असैन्य परमाणु समझौते पर हुए हस्ताक्षर इस रिश्ते में उछाल की बानगी थी लेकिन वर्ष 2017 में डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदलने लगे। वर्ष 1991 के बाद अमेरिकी आकलन में भारत की हैसियत ऊपर होने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक प्रगति थी। करीब डेढ़ दशक तक इसकी उच्च वृद्धि दरों ने अमेरिका को यह यकीन दिला दिया था कि भारत को तेजी से उभरते सर्वाधिकारवादी चीन के बरक्स खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के तौर पर भारत के स्थायित्व ने भी अमेरिका को प्रभावित किया, खासकर 1991 में यूगोस्लाविया और सोवियत संघ के पतन के बाद। हालांकि 2019 आने तक दुनिया के समक्ष यह साफ हो चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था गत छह वर्षों से पतन की राह पर है। इसके अलावा 2014 के बाद से ही सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाएं और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देश भर में छिड़े विरोध प्रदर्शन राजनीतिक एवं सामाजिक ध्रुवीकरण को बयां कर रहे हैं। ये परिस्थितियां अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

आर्थिक गिरावट और इससे जल्द उबरने की संभावना खारिज करने के बाद चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करने के लिए ट्रंप की तरफ से पेश 'हिंद-प्रशांत' की अवधारणा भी सवालों के घेरे में आ गई है। बीते दशक में भारत और अमेरिका ने 15 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले रक्षा सौदों पर दस्तखत किए हैं और हाल ही में अमेरिका ने एक अरब डॉलर मूल्य की नेवल गन बेचने की भी पेशकश रखी है। लेकिन भारत को चिढ़ाने वाली बात यह है कि एक औपचारिक सहयोगी नहीं होने से अमेरिका अब भी उसे संवेदनशील सैन्य तकनीक देने से मना कर देता है। संप्रभुता कहती है कि भारत को रूस से एस-400 मिसाइलें खरीदने का हक है, वहीं इस हवाई सुरक्षा प्रणाली के चलते अमेरिका के साथ नजदीकी सैन्य संबंध अवरुद्ध हो जाते हैं। अमेरिका रूस को अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरे के तौर पर देखता है। अगर एक गठबंधन का अभाव अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है तो यह अमेरिका को भारत के साथ संबंधों की व्यवहार्यता को लेकर संदिग्ध बना देता है।

कारोबारी मुद्दे भी उनके रिश्ते में अहम हैं। भारत की लालफीताशाही और संरक्षणवादी शुल्क अमेरिका को नागवार गुजरते हैं। ये मुद्दे एक व्यापारिक साझेदार के तौर पर भारत की चमक फीकी कर देते हैं। अमेरिकी निर्यात का महज 2.1 फीसदी ही भारत आता है और 2.2 फीसदी आयात भारत से होता है। वहीं भारतीय आयात का 15 फीसदी अमेरिका से आता है और उसके निर्यात का 16 फीसदी अमेरिका को जाता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पतनोन्मुख होने के बीच चीन ने अपनी बेल्ट एवं सड़क पहल (बीआरआई) का विस्तार दुनिया भर में कर अपनी आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन किया है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों और भारत के सारे पड़ोसियों ने बीआरआई का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है। चीन के वित्तीय घूंसे ने उसे इन अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर स्थापित कर दिया है। यह म्यांमार और बांग्लादेश को सबसे बड़ा हथियार विक्रेता भी है। हिंद महासागर में उसकी बढ़ती मौजूदगी एक प्रभावशाली दक्षिण एशियाई ताकत के तौर पर भारत की हैसियत के समक्ष मुश्किल सवाल खड़े करता है।

घरेलू मोर्चे पर सीएए पारित होने के बाद देश भर में उठे विरोध के स्वरों ने भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक छवि को लेकर अमेरिका में बहुतों को आशंकित कर दिया है। उसके पहले भी अमेरिकी विदेश विभाग ने गत वर्ष जून में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है। भारत ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा था कि किसी विदेशी सरकार को उसके अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

वॉशिंगटन में दिसंबर में हुई 2प्लस2 बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने कहा कि अमेरिका हर जगह अल्पसंख्यकों एवं धार्मिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर फिक्रमंद रहता है। उन्होंने हिंद-प्रशांत भागीदारी में विश्वास जताते हुए कहा कि यह सहयोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।

अमेरिकी अधिकारियों के विचार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। पॉम्पिओ का बयान घरेलू तनावों के चलते भारत पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई भी दबाव डालने की बात नकारता नजर आया लेकिन अमेरिकी सांसदों का रवैया कुछ अलग कहानी ही कहता है। अगस्त के बाद कश्मीर के हालात और नागरिकता कानून के विरोध में उठे विरोध से निपटने के लिए किए गए ताकत के इस्तेमाल का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान लगाए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने का मुद्दा उठाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर पर चर्चा के लिए अमेरिकी संसद की विदेश समिति से मिलने से मना कर दिया तो यही बात उठी कि मानवाधिकार का मुद्दा उठाने वाले अमेरिकी सांसद ऐसी हरकत की उम्मीद किसी तानाशाही सरकार से करते हैं, भारत से नहीं।

सामरिक भागीदारी के बावजूद भारत और अमेरिका का रिश्ता वर्ष 2020 में हिलोरें मारती तरंगों से ही गुजरेगा। लेकिन भारत और चीन के बीच आर्थिक फासला होने से हिंद-प्रशांत के लिए ट्रंप की योजना में भारत की अहमियत को लेकर सवाल खड़े होते हैं। चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में चार गुने से भी अधिक है। इसी तरह चीन का 177.6 अरब डॉलर का रक्षा बजट भारत का तिगुना है। जहां चीन वर्ष 2050 तक विश्व स्तरीय सेना बनाने की मंशा रखता है, वहीं भारत को अपने सशस्त्रबलों को आधुनिक बनाना भी मुश्किल हो रहा है।

अमेरिका पर अपनी आर्थिक एवं सैन्य निर्भरता से भारत जहां जलता है वहीं अमेरिका को इससे कोफ्त होती है। ट्रंप प्रशासन समृद्ध सहयोगी पसंद करता है क्योंकि इस तरह वे साझा खतरों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

नए साल की शुरुआत में भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति अनिश्चित नजर आ रही है। भले ही नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे व्यापक प्रदर्शन रोजगार के मौके कम होने से उपजे गुस्से को भी बयां करते हैं लेकिन सरकार आर्थिक एवं सामाजिक-राजनीतिक संकट से उबरने के लिए वित्तीय एवं मानव संसाधनों के इस्तेमाल का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। इसके बजाय नागरिकता कानून पर अमल की दिशा में बढ़ना यह दिखाता है कि वह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से दूर होने की कोशिश से अस्थिरकारी संघर्षों के पनपने की चेतावनी को नजरअंदाज करती है।

हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन वर्ष 2020 यह बताएगा कि क्या घरेलू स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक मुश्किलों में घिरा भारत अमेरिका के साथ सामरिक सहयोग के लिहाज से बेमेल है या दोनों देशों के बीच करीबी सामरिक संबंध संभव हैं?

(लेखिका सेंटर फॉर पीस ऐंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, नई दिल्ली की संस्थापक प्रोफेसर हैं)

देश के बुनियादी विकास में तेजी की तैयारी

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

एनआईपी टास्क फोर्स ने अगले साल बुनियादी क्षेत्र के लिए सरकारी फंड में भारी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। क्या सरकार बुनियादी क्षेत्र के लिए ज्यादा वित्तीय खर्च की मांग को नजरदांज कर सकती है?

बीते वर्ष के अंतिम दिन एक संवाददाता सम्मेलन में टास्क फोर्स ऑन नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर 2019-25 की रिपोर्ट जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 2020-21 का आम बजट पेश करने से एक महीना पहले मीडिया से मिलने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, यह कि उन्हें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए देश को यह बताने में देरी का कोई कारण नजर नहीं आता कि वरिष्ठ सरकारी अधिकरियों के एक समूह ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को पटरी पर लाने के लिए क्या सिफारिश की है।

अमूमन बजट से पहले वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय मीडिया से दूर ही रहते हैं। ऐसा कम ही होता है कि वित्त मंत्रालय का कोई अधिकारी बजट पेश होने से चार हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वित्त मंत्री तो दूर की बात है। बजट को लेकर गोपनीयता बरती जाती है और बजट में की जाने वाली घोषणाओं को गोपनीय रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाते हैं। इसलिए, बजट से एक महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से परहेज किया जाता है। ऐसी स्थिति में बजट से एक महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही रहा होगा कि सभी को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि सरकार बुनियादी ढांचे में ज्यादा निवेश को लेकर गंभीर है।

हालांकि, इस प्रक्रिया में एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट के बारे में कुछ अहम संकेत दिए होंगे। उदाहरण के लिए टास्क फोर्स के अनुमान के मुताबिक 2019-20 में सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) की नॉमिनल वृद्धि करीब 8 फीसदी रहेगी जबकि पहले इसके 12 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। नॉमिनल संदर्भ में 2019-20 में जीडीपी के 205.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 2018-19 में 190 लाख करोड़ रुपये थी। टास्क फोर्स के मुताबिक नॉमिनल जीडीपी के 2020-21 में 10.5 फीसदी और 2021-22 में 12 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है।

आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी और वित्त मंत्रालय तथा दूसरे प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य हैं। तो क्या टास्क फोर्स के आंकड़ों से आपको मौजूदा आर्थिक वृद्धि परिदृश्य की थाह नहीं मिलती है जिसमें अगले वर्ष का बजट बनाया जा रहा है? हर कोई जानता है कि आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ रही है लेकिन इस रिपोर्ट के जारी होने से पहले सरकार में किसी ने भी नहीं कहा था कि 2019-20 में नॉमिनल वृद्धि केवल 8 फीसदी रहेगी। जाहिर है कि सरकार के कर राजस्व पर इसका प्रतिकूल असर होगा।

एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट से यह पता भी चलता है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अगले बजट में क्या हो सकता है। 2018-19 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की सकल बजट सहायता 1.39 लाख करोड़ रुपये रही थी जो विभिन्न मदों के तहत सभी पूंजीगत व्यय के लिए सरकार की कुल बजट सहायता का 44 फीसदी है। 2019-20 में कुल पूंजीगत खर्च के लिए सकल बजट सहायता में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बजट सहायता का हिस्सा 45 फीसदी यानी 1.53 लाख करोड़ रुपये है। टास्क फोर्स के मुताबिक 2020-21 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये के बजट सहायता की जरूरत होगी। अगर अगले वर्ष भी 44-45 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रहती है तो पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार की सकल बजट सहायता 22 फीसदी बढ़कर 4.13 लाख करोड़ रुपये बढ़नी चाहिए। 22 फीसदी से कम बढ़ोतरी का मतलब होगा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी समिति की रिपोर्ट ही स्वीकार नहीं की है।

एनआईपी टास्क फोर्स का साथ ही कहना है कि बुनियादी क्षेत्र के लिए सरकार का कुल खर्च 2020-21 में 21 फीसदी बढ़कर 4.58 लाख करोड़ रुपये होना चाहिए जो 2019-20 में 3.77 लाख करोड़ रुपये है। यह एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है क्योंकि 2019-20 में बुनियादी क्षेत्र के लिए कुल व्यय में केवल 6.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।

सरकार के कुल पूंजीगत खर्च (भारतीय रेल सहित सार्वजनिक इकाइयों की आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों सहित) में बुनियादी क्षेत्र पर कुल सरकारी खर्च का हिस्सा 38 से 43 फीसदी के बीच रहा है। अगर यह हिस्सा 2020-21 में बरकरार रहता है तो अगले साल के बजट में सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में 21 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 10.65 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होना चाहिए।

इन आंकड़ों से साफ है कि एनआईपी टास्क फोर्स ने अगले साल बुनियादी क्षेत्र के लिए सरकारी फंड में भारी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। क्या सरकार बुनियादी क्षेत्र के लिए ज्यादा वित्तीय खर्च की मांग को नजरदांज कर सकती है? और क्या बजट से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी करने के फैसले का मकसद सरकार के भीतर प्रभावशाली वर्गों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत स्वीकार करने और राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के लिए ज्यादा दबाव डालना है।

कानाफूसी

मीठा और गर्म प्रचार

दिल्ली में चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए टिकट उम्मीदवारों ने अनोखे उपहारों से मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आजाद सिंह हैं, जो मतदाताओं को गुड़ और कैलेंडर बांट रहे हैं। हर कोई यही कहेगा कि ये इस समय के लिहाज से सबसे उपयुक्त तोहफे हैं क्योंकि नया साल शुरू हुआ है और पिछले पखवाड़े में मौसम अब तक का सबसे ठंडा रहा है। गुड़ और कैलेंडर को कपड़े के थैले में पैक किया गया है, जिस पर फोन नंबर लिखे हैं। यहां कपड़े के थैले का जिक्र करना इसलिए अहम है क्योंकि थैले पर छपा है- 'प्लास्टिक को ना कहें'। पिछले सप्ताह ये तोहफे वसंज कुंज में बांटे गए। सिंह के समर्थक तोहफे को लेने से इनकार करने वालों को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जो लोग घर पर नहीं थे, उन्हें भी ये थैले अपने दरवाजे पर टंगे मिले।

चौथी बार खुली किस्मत

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस बात से खफा हैं कि उन्हें इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक विशेष बल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को अपने करीब 15 साल के इतिहास में पहली बार सूची में रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनडीआरएफ ने चौथी बार झांकी सौंपी थी। पहले तकनीकी या अन्य वजहों से जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद झांकी को तैयार कर रही टीम इस बार अपनी किस्मत को जानने के लिए उत्सुक थी। जब पिछले शुक्रवार को 22 भागीदारों की सूची की घोषणा की गई तो उनके पास पास खुशी मनाने का मौका था। झांकी में बचाव कार्यों के दौरान बल की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी।

आपका पक्ष

विश्व को अमेरिका-ईरान टकराव से घाटा

हाल में अमेरिका ने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई। ईरान कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक देश है और विश्व के कई देश ईरान से कच्चा तेल आयात करते हैं। भारत भी उससे कच्चे तेल का आयात करता है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था और अन्य देशों को ईरान से तेल आयात करने को मना किया था। इसके बाद तेल कीमतों में उछाल आई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। भारत में भी पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ गए। इसके अलावा भारत का ईरान को आयात निर्यात भी प्रभावित हुआ है। भारत का कारोबार अमेरिका और ईरान दोनों देशों से होता है। भारत के लिए दोनों देश काफी महत्त्व रखते हैं। कारोबार के मामले में भारत के ईरान से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भी ईरान भारतीय मुद्रा में तेल निर्यात पर सहमत हो गया था। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव गंभीर स्थिति तक पहुंच जाता है तो इससे विश्व के कई देशों को भी नुकसान होगा। अमेरिकी हमले के बाद विश्व युद्ध छिड़ने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। इस समय सभी देशों को संयम से काम लेना चाहिए और युद्ध के हालात नहीं बने इसपर सोचना चाहिए। युद्ध से देश को तो नुकसान होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ता है। आज कई देश परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में अगर एक भी परमाणु बम इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है जैसा कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर पड़ा था। अत: विश्व के सभी देशों को अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को रोकने की दिशा में विशेष पहल करनी चाहिए और दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने का संदेश देना चाहिए।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अन्य देशों को आगे आना चाहिए

गौरव कुमार, नई दिल्ली

बजट से मिलेगी बदलाव की उम्मीद

सरकार इस आम बजट को इस अनुमान के आधार पर तैयार कर सकती है कि इस साल में देश की विकास दर में अच्छी बढ़ोतरी हो। साल 2020 का बजट प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सरकार देश को आर्थिक सुस्ती से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। साल 2020 में विकास दर 6 से 6.5 फीसदी विकास होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में तेजी से वापसी के संकेत दिख रहे हैं। शेयर बाजार चालू वित्त वर्ष में मुनाफे में 25 फीसदी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो नए साल में शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंच सकता है। सरकार को आम लोगों के साथ निवेशकों की धारणा भी सुधारने की जरूरत है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध सुलझाने की दिशा में भी बाजार में तेजी आ सकती है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी असर देखने को मिल सकता है।

अमित जायसवाल, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।